want to know whether the Government is having any negotiations with the Russian Government in pursuance of that treaty?

SHRI D. K. BOROOAH: In pursuance of that as also of the earlier co-operation with the Soviet Union, we have already entered into large scale arrangements with Soviet Union for onshore drilling, that is, drilling on land in different parts of India. Our only collaborator for on-shore drillings in our territory is the Soviet Union. But, so far as off-shore drilling is concerned, Soviet Union have no expertise in this line and there has been no proposal in that regard.

SHRI B. V. NAIK: The location of the drilling of the Bombay High is at a considerable distance from the shore and outside, as far as I know, the territorial waters of this country. There is going on in the United Nations a controversy, called, seabed controversy. Is there any objection raised by any of the other countries to our taking up drilling in this area called 'Bombay High' because it falls in the high seas? Is there any law, international or national, which forbids a country so that we may take appropriate action?

SHRI D. K. BOROOAH: This is a matter which has certainly to be considered. But one thing is certain. We have grave objection and we will oppose tooth and nail any interference or any attempt by any foreign country to drill in these areas.

SHRI S. A. SHAMIM: This question must be expunged.

**Completion of Gandak Project**

*540. SHRI BIBHUTI MISHRA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether Government has fixed a definite target date to complete Gandak Project; and

(b) if so, the date so fixed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) and (b). The work on the Gandak Project is expected to be completed by 1976-77.

**श्री विभूति मिश्र** : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि जब से गंडक योजना की शुरूवात हुई तब से अब तक सरकार ने कितनी दफा टार्गेट डेट्स को बदला, और जिन टार्गेट डेट्स को रखा उन में क्यों नहीं इस योजना की पूर्ति हो पायी ? आखिर सरकार ने जो 1976-77 का टार्गेट रखा है उस में गंडक योजना पूरी तरह से कामयाब हो जायगी ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : यह गंडक योजना बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यान्वित करने की जो तिथियां हमें बतायी हैं हम उसी के आधार पर सदन को सूचना देते रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार ने बताया कि 1976-77 में गंडक योजना के पूरा हो जाने की पूरी सम्भावना है ।

**श्री विभूति मिश्र** : अध्यक्ष जी, मैं इस सदन में शुरू से पूछता रहा हूं इन-फ्लेशन है, 120 करोड़ रु० इस पर खर्च हो चुका है और तीन, चार लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होती है, सारा पैसा केन्द्रीय सरकार का लगता है, केन्द्रीय सरकार के सारे मंत्री कहते हैं कि जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो इतना इनफ्लेशन हो रहा है, आप ने जो टार्गेट डेट बतायी क्या उस में इस योजना को निश्चित रूप से पूरा करना चाहते हैं ? या फिर देश में इनफ्लेशन बढ़ाना चाहते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है हम इस बात की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि 1976–77 तक यह योजना अवश्य पूरी हो जाए । जहां तक मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध है वह एक बड़ा लम्बा सवाल है और इस वास्ते इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है ।

**श्री विभूति मिश्र** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । 120 करोड़ खर्च कर चुके हैं। इनपलेशन होती जाती है । मूल्य बढ़ते जाते हैं। आप इसका जवाब नहीं दिलवाते हैं कि जो टारगेट रखी है क्या उस टारगेट डेट तक इसको अवश्य पूरा कर लिया जाएगा ? पूरा आप नहीं करते हैं और जवाब भी नहीं देते हैं । इसकी जवाबदेही किस की है ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठता है । मिनिस्टर साहब कुछ और बताना चाहें तो बता सकते हैं ।

**श्री विभूति मिश्र** : रुपया इनका है । क्यों पूरा नहीं करवाते हैं ? किस की जवाब देही है ?

SHR A. P. SHARMA: We were given to understand that if the Bihar Government proposes or recommends, then, this Gandak project will be taken up by the Central Government. So far as we know, Sir, the Chief Minister of Bihar has already written to the Central Government. May I know whether the Central Government has decided to take up this project?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD: This is a matter which has been raised earlier in the House and has been replied to regarding an-other question put by Shri Bibhuti Mishra and the Planning Minister had said that it is not acceptable.

MR. SPEAKER: The Minister is from Bihar and Members are from Bihar.

SHRI A. P. SHARMA: In this House we were assured that this will be taken up provided the Bihar Government agrees and now the Government replies that they have considered and they have decided not to do it.

**श्री डी० एन० तिवारी** : गंडक नहर सारन जिले से हो कर जाने वाली है । सारा काम ठप्प पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है । चार पांच महीने से नहीं हो रहा है । सारा स्टाफ बैठा हुआ है ।

दूसरी बात यह है कि मेन चैनल बनाने की ही कोशिश हो रही है लेकिन सबसिडिएरी चैनल्ज नहीं बनाई जा रही है । इसका नतीजा यह हो रहा है कि खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है । क्या मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे कि सबसिडिएरी चैनल्ज बनाई जाएं ताकि खेतों को पानी दिया जा सके, उसकी व्यवस्था हो सके ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उस के सम्बन्ध में बिहार सरकार के जो अधिकारी तथा मुख्य अभियंता आए थे उन के साथ इस की चर्चा हुई थी और उन लोगों ने कहा कि पिछले साल चूंकि योजना में कुछ कटौती हो गई इसलिए काम में थोड़ी शिथिलता आ गई थी । अब माननीय सदस्य ने जिस नहर और उस की शाखा नहर की ओर संकेत किया है, उस पर काम तेजी से शुरू किया जाएगा ।

SHRI PRABODH CHANDRA: Many of the projects are held up because of inter-State quarrels. Is there any

proposal with the Central Government to take up these projects and complete them in time rather than cause delay which is causing the country loss to the tune of billions of rupees?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD: Irrigation is a State subject and these projects have got to be executed by the State Government. If there are inter-State problems we do try settle and sort out such problems. After they are sorted out, when such projects are ready, they have to be executed by the concerned State Governments.

**माल भाड़े और यात्री किराये में वृद्धि की प्रतिशतता**

+

*541. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के वर्ष 1970 में प्रति टन और प्रति किलोमीटर माल भाड़ा और तीसरे दर्जे का प्रति यात्री प्रतिकिलोमिटर किराया अलग अलग क्या था और अब क्या है ;

(ख) वर्ष 1972-73 में उपरोक्त दरों में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई; और

(ग) यदि रेलवे के माल भाड़े और किराये में वृद्धि हुई है तो जन साधारण के हित को ध्यान में रखते हुए अधिक सुविधायें देने के लिए कदम उठाये जायेंगे?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शकी कुरैशी) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) और (ख). प्रतिभाड़ा मीटरिक टन किलोमीटर और तीसरा दर्जा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर औसत आय और उस में 1970-71 की तुलना में 1972-73 में हुई प्रतिशत वृद्धि ।

| | 1970-71 (पैसे) | 1972-73 (पैसे) | 1970-71 की तुलना में 1972-73 में हुई प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|
| प्रति मीटरिक टन किलोमीटर प्रति औसत आय | 5.43 | 5.74 | 5.71 |
| तीसरा दर्जा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर आय | | | |
| मेल | 2.92 | 2.96 | 1.37 |
| असाधारण | 1.98 | 2.02 | 2.02 |

(ग) जन साधारण को और सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) तीसरे दर्जे में अधिक प्रतीक्षालयों की व्यवस्था ।

(2) पीने के ठंडे पानी का प्रबन्ध ।

(3) अतिरिक्त टिकट खिड़कियां के खोलने की व्यवस्था ।

(4) जयन्ती जनता गाड़ियां चलाना।

(5) अतिरिक्त गाड़ियां चलाना/ वर्तमान गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाना ।

(6) स्टेशनों पर घोषणा कक्षों की स्थापना ।